संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख) सरकार बातचीत द्वारा समझौता करने पर विश्वास करती है और सभी बकाया मुद्दों पर व्यापक समझौता करने का भरसक प्रयास करेगी। तथापि, केवल उन्हीं लोगों के साथ बातचीत करना सम्भव है जो हिंसा त्याग दें और संविधान के ढांचे को स्वीकार करें। इस प्रकार सरकार पंजाब में शान्ति बहाल करने और प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया पुनः चालू करने के लिए उचित कार्रवाई शुरू करेगी।

Bomb explosion at Indira Gandhi International Airport

235. SHRI SHANTI TYAGI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether a bomb explosion took place at the Indira Gandhi International Airport shortly after midnight on Monday, the 24th June, 1991;

(b) whether any culprits have been apprehended so far; and

(c) what new measures Government propose to take to ensure safety at this Airport?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) the area where the bomb exploded fell outside the security zone. This area and other similar areas have since been brought under watch.

अमरीकी प्रतिनिधि सभा द्वारा भारतीय सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में लगाई गई शर्तें

236. **श्री शान्ति त्यागी :**
श्री संतोष बागड़ोदिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने एक प्रस्ताव पारित करके भारतीय सैनिक अधिकारियों के प्रशिक्षण के संबंध में कुछ शर्तें लगाई हैं;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या उस प्रतिक्रिया से अमरीकी सरकार को अवगत करा दिया गया है ?

विदेश मंत्री (श्री माधव सिंह सोलंकी) : (क) अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने कैलिफोर्निया के रिपब्लिकन कांग्रेसमैन बिलहरगर द्वारा पेश संशोधन 14 जून, 1991 को स्वीकार किया था। इस संशोधन में भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक शिक्षा और प्रशिक्षण (आई.एम.ई.टी.) कार्यक्रम से संबद्ध निधियों के उपयोग के संबंध में मानवाधिकार की शर्तें लगाने की बात कही गई है।

(ख) इस संशोधन में अमरीकी राष्ट्रपति से इस बात का सुनिश्चय करने के लिए कहा गया है कि भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सैनिक शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त मानवाधिकारों और मानवीय मानकों को अच्छी तरह समझने तथा उनकी सराहना करने में मदद करे और उन्हें इन अधिकारों तथा मानकों को लागू करने के लिए सक्षम बनाए।

(ग) सरकार ने नीचे लिखे अनुसार वक्तव्य जारी किया है :

"ऐसे आदान-प्रदानों के लिए भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई शर्त स्वीकार करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, इन कार्यक्रमों का आशय आपसी लाभ है और भारत इसका एकमात्र लाभ उठाने वाला देश नहीं है। इस संशोधन का प्रच्छन्न आशय हमारी सशस्त्र सेनाओं पर लांछन लगाना है जो लगातार चल रही व्यापक आतंकवादी हिंसा और अत्यधिक भड़काने वाली कार्यवाहियों से होते